अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक मार्गदर्शक

लेखक- परकला प्रभाकर (पूर्व संचार सलाहकार, आंध्र प्रदेश सरकार)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

14 अक्टूबर, 2019

"नेहरूवादी समाजवाद की आलोचना करने के बजाय, भाजपा को राव-सिंह आर्थिक नीति को अपनाना चाहिए।"

देश में आर्थिक मंदी को लेकर हर तरफ चिंता व्याप्त है। हालांकि सरकार अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रही है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में निर्बाध रूप से प्रतीत हो रहे डेटा दर्शाते हैं कि एक के बाद एक सेक्टर गंभीर रूप से कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। निजी खपत संकुचित हो रही है और 3.1% के 18-तिमाही के निम्न स्तर पर आ चुकी है। ग्रामीण उपभोग भी गंभीर स्थिति में है और शहरी मंदी की दर से दोगुना है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों द्वारा ऋण लेने की दर स्थिर हो गयी है। शुद्ध निर्यात ने कोई खास वृद्धि नहीं दिखाई दे रही है सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में केवल 5% दर्ज करने के साथ यह छह साल के निचले स्तर पर है। और बेरोजगारी 45 साल की अपनी उच्चतम स्तर पर है।

हालांकि, सरकार को अभी तक इसका आभास नहीं है कि ये सभी आंकड़ें अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं और इस बात का भी सबूत बहुत कम उपलब्ध है कि सरकार इन चुनौतियों को संबोधित करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई रणनीतिक दृष्टिकोण अपना रही है।

कोई आर्थिक रोड मैप नहीं

यह समस्या मुख्य रूप से देश की अर्थव्यवस्था के बारे में विचारों के अपने सुसंगत सेट को विकसित न करने की भाजपा की अनिच्छा में निहित है। भारतीय जनसंघ के दिनों से समाज के नेहरूवादी समाजवादी स्वरूप की अस्वीकृति स्पष्ट थी। बीजेपी की सिफारिश को एक पूंजीवादी के रूप में शिथिल कहा जा सकता है और इस दौरान मुक्त बाजार की रूपरेखा भी व्यवहार में अप्रयुक्त रही है।

पार्टी की आर्थिक विचारधारा और इसकी अभिव्यक्ति मुख्य रूप से नेहरूवादी मॉडल को राजनीतिक स्पेक्ट्रम के झंझटों से दूर करने के लिए सीमित थी। गांधीवादी समाजवाद के साथ भाजपा की छेड़खानी इसकी स्थापना के बाद कुछ महीनों तक ही चली। आर्थिक नीति में, पार्टी ने मुख्य रूप से 'यह नहीं' का सिद्धांत अपनाया, बिना यह बताए कि उसकी अपनी नीति क्या है?

जिन मुद्दों ने पार्टी को देश के राजनीतिक प्रवचन के केंद्र चरण में और फिर केंद्र से विभिन्न राज्यों में सत्ता की गद्दी तक पहुंचा दिया, उनके पास आर्थिक रोड मैप तक मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, जब पहली बार, 1998 के बाद से 2004 तक, एक दृढ़ गैर-कांग्रेसी ने सरकार का नेतृत्व किया, तो आर्थिक नीति में कोई महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गये। वाजपेयी सरकार के तहत पार्टी का अभियान, 'इंडिया शाइनिंग' मतदाताओं को प्रभावित करने में विफल रही।

इसका मुख्य कारण यह था कि लोगों ने पार्टी के किसी भी उद्देश्य को उतना बेहतर नहीं माना जितना होना चाहिए। इसलिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 2004 के आम चुनाव में विकास और अर्थव्यवस्था के एजेंडे ने पार्टी को निराशा क्यों किया? पार्टी का वर्तमान नेतृत्व शायद इससे अब अवगत हो गया है। इसने इस बार इस बात का ध्यान रखा कि फिर से चुनाव के दावे के रूप में अपनी सरकार के आर्थिक प्रदर्शन की पेशकश न करें। इस बार उन्होंने, बुद्धिमानी से, एक मजबूत राजनीतिक, राष्ट्रवादी, सुरक्षा मंच चुना।

राव-सिंह नीति

वर्तमान आर्थिक संकट में आवश्यक तत्व नेहरूवादी नीति ढांचे पर भाजपा की अनिच्छा है, जिसकी वह आलोचना कर रहा है। पथ-प्रदर्शक की पुनरावृत्ति ने पी.वी. नरसिम्हा राव और उनके आर्थिक सलाहकार मनमोहन सिंह आज भी अनछुए हैं। पिछले कई वर्षो से राव-सिंह नीति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किये गये। कांग्रेस राव जी की स्मृति को अपने संगठनात्मक मूल धारणा से मिटाकर नेहरूवादी अर्थशास्त्र के शर्तों का परित्याग करने के विचार के साथ सामने आई थी। लेकिन इसने डॉ. सिंह को बनाए रखते हुए 1991 की पारी से अपना जुड़ाव बनाए रखा।

एक अलग मोड़

फिर भी भाजपा नेहरूवादी आर्थिक ढांचे पर हमला करना जारी रखती है। लेकिन पार्टी थिंक टैंक यह सोचने में विफल रहती है कि इस तरह का हमला एक राजनीतिक हमला है, यह आर्थिक संकट की समस्या से नहीं निपट सकता है। इसके विकल्प के निर्माण का एजेंडा अभी तक सफल नहीं हो सका है। आधुनिक बाजार संचालित, भूमंडलीकृत दुनिया में 'एकात्म मानववाद' जैसे निर्माणों को व्यावहारिक नीतिगत पहल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

जब एक कांग्रेसी नेता सरदार पटेल भाजपा की राजनीतिक परियोजना में एक आइकन बन सकते हैं तो इसी तरह, राव, एक कांग्रेसी, कि आर्थिक नीति को क्यों नहीं अपनाया जा सकता है। हालांकि, भाजपा ने राव की 1991 नीति वास्तुकला को ना तो चुनौती दी और ना ही उसे खारिज किया, लेकिन इसे पूरी तरह से अपनाया भी नहीं। वर्तमान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है और यदि बेहतर नीति के साथ इस पर कार्य किया गया तो इससे बाहर भी निकला जा सकता है।

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**

1. वित्त वर्ष 2015 में निजी निवेश की दर 30.1% हुआ करती थी पर 2019 में यह घटकर 28.9% रह गई है।
2. आर.बी.आई. ने भारतीय अर्थव्यवस्था के जी.डी.पी. ग्रोथ रेट के पूर्वानुमान को घटाकर 6.9% कर दिया है।
3. मंदी से निकलने में राव सिंह नीति सहायक हो सकती है, जो 1991 में आई थी।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements in the context of present Indian economy.**

1. The rate of private investment was 30.1% in FY 2015 but it has come down to 28.9% in 2019
2. RBI has lowered the GDP growth forecast of the Indian economy to 6.9%.
3. Rao Singh policy can be helpful in coming out of recession, which came in 1991.

statements given above are correct?

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3

(c) 1 and 3 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने हेतु एक बेहतर विकल्प 1990 के दशक के शुरू के वर्षों में अपनाया गया 'राव-सिंह मॉडल' हो सकता है। क्या आप सहमत हैं? (250 शब्द)

A better option to get the Indian economy out of recession may be the 'Rao-Singh model', which was adopted in the early 1990. Do you agree?

(250 Words)

नोट : 12 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (a) होगा।